

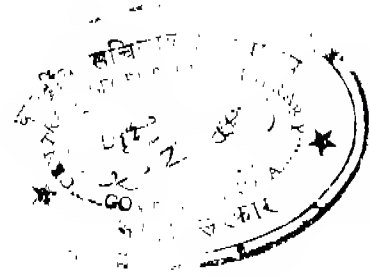


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 452]
No. 452]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 1987/भाद्र 18, 1909
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 1987/BHADRA 18, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1987

अधिसूचना सं. 7514

आय-कर

सा. का. नि. 756 (अ) :—आय और पूँजी पर कर की बाबत दोहरे कराधान का परिहार करने और राज्य वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और नार्वे साम्राज्य के बीच संलग्न अभिसमय, वर्ष उन्नीस सौ छियासी में, जो ऐसा वर्ष है जिसमें उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, दोनों सन्निदाकारी राज्यों द्वारा उनकी विधियों के अधीन अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा हो जाने के बारे में, उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 31 के पैरा 1 की अपेक्षानुसार, एक दूसरे को अधिवृचित किए जाने पर, प्रवृत्त हुआ है;

87/1063/GI

(1)

अतः केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44 क, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1961 (1961 का 7) की धारा 2 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

उपबंध

आय तथा पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य

और

नार्वे राज्य

के बीच

अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और नार्वे राज्य की सरकार आय तथा पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के

परिहार और राजस्व के अपवर्धन को रोकने के लिए अभिसमय संपन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं।

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. जिन वर्तमान करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विधेयतः इस प्रकार हैं :

(क) भारत में;

(i) आयकर जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत उस पर लगने वाला कोई भी अधिभार शामिल है;

(ii) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अंतर्गत लगाया जाने वाला अतिकर;

(iii) धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अंतर्गत लगाया जाने वाला धन कर;

(जिन्हें इसके बाद “भारतीय कर” कहा जाएगा)।

(ख) नावों में:—

(i) आय पर राष्ट्रीय कर
(इभतेक्त्सस्कत तिल स्तातेन);

(ii) आय पर प्रमण्डल नगरपालिका कर
(इभतेक्त्सस्कत तिल फिलकेमकुम्मुनेन);

(iii) आय पर नगरपालिका कर
(इभतेक्त्सस्कत तिल कुम्मुनेन);

(iv) कर समकरण निधि में राष्ट्रीय योगदान
(फेल्लेस्कत तिल स्क्तेफुरदेल्सफुन्ने);

(v) पूंजी पर राष्ट्रीय कर
(फुरमुएस्कल तिल स्तातेन);

(vi) पूंजी पर नगरपालिका कर
(फुरनुएस्कल तिल कुम्मुनेन);

(vii) अंतः सागरी पेट्रोलियम संसाधनों तथा क्रिया-कलापों एवं उससे संबंधित कार्य, जिसमें उत्पादित पेट्रोल का पाइपलाइन से परिवहन भी शामिल है, के लिये खोज तथा शोषण से प्राप्त आय तथा पूंजी से संबंधित राष्ट्रीय कर (स्कत तिल स्तातेन वेदरुन्दे इस्तेक्त्त उग फुरमुए ई फुरबिदेलसे मेद उन्देरसंकलसे एत्तेर उग उतनितेलसे आव उन्देर-शुइस्के पेट्रुलेइमसफुरेकुन्सतेर उग देरतिल

बिनसेत विरकुसुमहेत उग अरयेइव, हेरुन्दर रुरलेदलिस तरन्सपुरत आव उतयुन्नेत पेट्रुलेउम)

(viii) अनिवासी कलाकारों के पारिश्रमिक पर राष्ट्रीय कर (आवयिफ्त तिल स्तातेन आव हुनुरारेर सुम तिलफलेर कुन्सतेरे बुसत ई उतलन्ने);

(ix) नाविक का कर (शुभाभसस्कात्त)

(जिन्हें इसके बाद “नावों का कर” कहा जाएगा);

2. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करने पर भी लागू होगा जो वर्तमान अभिसमय पर रस्ताधर किये जाने की तारीख के पश्चात् पैरा-ग्राफ 1 में उल्लिखित वर्तमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा लगाये जायें। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किये जाते हैं।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएँ

1. इस अभिसमय में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:—

(क) “भारत” शब्द से अभिप्रेत है भारत का राज्य-क्षेत्र और उसमें शामिल है राज्य क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार हों;

(ख) “नावें” शब्द से अभिप्रेत है नावें राज्य जिसमें नावें राज्य के राज्य क्षेत्रीय सागरखण्ड बाहर का वह कोई भी क्षेत्र शामिल है जहां नावों के कानूनों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार नावें राज्य समुद्र-तल तथा अवमृदा और उनके प्राकृतिक संसाधनों के सम्बन्ध में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता हो; इस शब्द में स्वालवार्ड, जान मायेन अथवा योरोप से बाहर नावों के अधीन के राज्य शामिल नहीं हैं।

(ग) “एक संविदाकारी राज्य” और “दूसरा संविदाकारी राज्य” पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा नावें अभिप्रेत हैं;

“र” शब्द से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, रतीय कर अथवा नावों का कर अभिप्रेत है, न्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी उन करों के संबंध में किसी चूक अथवा भूल संदर्भ में देय हो जिन पर यह अभिसमय लागू ता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाया 7 अर्थदण्ड हो;

- (ङ) "व्यक्ति" शब्द में व्यक्ति, कंपनी और ऐसी कोई भी अन्य सत्ता शामिल है जो अलग अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत कर लगने योग्य इकाई मानी जाती है;
- (च) "कंपनी" शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई भी ऐसी सत्ता अभिप्रेत है, जो अलग अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कंपनी अथवा निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है;
- (छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;
- (ज) "सक्षम प्राधिकारी" शब्दों से भारत के मामले में अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि; और नार्वे के मामले में, वित्त अथवा सीमा शुल्क का मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (झ) "राष्ट्रिकों" शब्द से अभिप्रेत है किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;
- (ञ) "अन्तर्राष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन जो किसी संविदाकारी राज्य द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो।

2. जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो वहाँ परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, "संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा व्यक्ति,

जिस पर, उस राज्य के कानून के अन्तर्गत, उसके अधिवास, निवास, प्रबंधस्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कमीटी के कारण, वहाँ कर लगाया जा सकता है।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहाँ उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जायेगी।

- (क) उसे उस राज्य का निवासी माना जायगा जहाँ उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);
- (ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसको किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा जिसमें वह आदतन रहता हो;
- (ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जायेगा जिसका वह राष्ट्रिक है;
- (घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजन के लिए, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ उद्यम का कारोबार संपूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;

- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कोई माल गोदाम जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो;
- (ज) फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वन, बागवानी अथवा तत्संबंधी कार्य किये जाते हैं;
- (झ) कोई परिसर जिनका प्रयोग विक्रय स्थल अथवा आदेश प्राप्त करने अथवा मंगवाने के लिए किया जाता है;
- (ञ) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है;
- (ट) कोई भवन, स्थल, कोई निर्माण कार्य, संयोजन अथवा प्रतिष्ठापन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्य, परन्तु केवल जहां ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप अन्य ऐसे स्थलों, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों यदि कोई हों; के साथ-साथ तीन महीनों से अधिक समय के लिये चालू रहते हों;
- (ठ) किसी उद्यम द्वारा कर्मचारियों अथवा अन्य कर्मिकों अथवा ऐसे उद्देश्य के लिए उद्यम द्वारा नियोजित कर्मिकों के जरिये ऐसे स्थान पर सेवाएं प्रस्तुत किया जाना, जिसमें परामर्शदात्री सेवायें भी शामिल हैं, परन्तु केवल वहां जहां इस तरह के कार्यकलाप (उसी अथवा उससे संबंधित परियोजना के लिये) देश के अन्दर बारह महीने की किसी भी अवधि के भीतर कुल मिलाकर छह महीने से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिये जारी रहते हों।
3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उल्लेखों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जायेगा :
- (क) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य के केवल भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य का स्टॉक रखना;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किये जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टॉक रखना;

(घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;

(ङ) उद्यम के लिए, अन्य रूप से विज्ञान देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा अन्य ऐसे कार्यकलापों के संबंध में जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना।

तथापि उप पैराग्राफ (क) से (ङ) तक के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में उक्त उप-पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट उद्देश्य से भिन्न किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए कारोबार का कोई भी अन्य निश्चित स्थान रखता हो।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अधिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा है तो उस उद्यम का प्रथमोलिखित राज्य में उस स्थिति में एक स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा, यदि

(क) उसे उस राज्य में उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आमतौर से उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसको गतिविधियां उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य खरीदने तक ही सीमित नहीं हो ;

(ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार न हो, परन्तु वह प्रथमोक्त राज्य में आमतौर पर वस्तुओं का अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से वस्तुओं और पण्य वस्तुओं को निर्यातित रूप से डिलीवरी करता हो ;

(ग) वह प्रथमोलिखित राज्य में, समग्रतः अथवा लगभग समग्रतः उद्यम ही के लिए अथवा उस उद्यम के लिए अथवा उद्यमों के लिए जो उस उद्यम को नियंत्रित करते हों, द्वारा नियंत्रित होता हो, अथवा उसी प्रकार के नियंत्रण के अधीन हो, आमतौर पर आदेश प्राप्त करता हो।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जायेगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन, जब ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम और अन्य उद्यमों की ओर से किये जाते हों जो उस उद्यम को नियंत्रित करते हों, उस उद्यम द्वारा नियंत्रित

हों अथवा उसी सामान्य नियंत्रण के अधीन हों, तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत एक स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जायेगा यदि यह पता चलता है कि एजेंट और उद्यम के बीच के लेन-देन बिना पूर्व-निश्चय की स्थिति में नहीं किये गये थे। उस मामले में पैराग्राफ 4 के उपबंध लागू होंगे।

6. यदि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा उससे नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इन तथ्य से ही उन दोनों में से किसी को दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जायेगा।

अनुच्छेद 6

अचल संपत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति से (जिसमें कृषि अथवा वन संपदा की आय शामिल है) प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल संपत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस पद में किती भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल संपत्ति के अवसाधन के रूप में संपत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए, अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिकल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार जलयान, नौकाएं तथा विमान अचल संपत्ति नहीं माने जायेंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध, उद्यम की अचल संपत्ति से अर्जित आय पर, तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के

माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो निम्नलिखित के कारण हुआ माना जा सकता है;

(क) उस स्थायी संस्थापन;

(ख) उस दूसरे राज्य में उसी अथवा उन्नी प्रकार की वस्तुओं अथवा तिजारती माल की बिक्री जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है; अथवा

(ग) उस दूसरे राज्य में की जाने वाली कारोबार संबंधी वैसी ही अन्य गतिविधियां अथवा उसी प्रकार की गतिविधियां जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती हों।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह उन्हीं या वैसे ही परिस्थितियों में उन्हीं या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्ययों को कटौतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों से किये गए हों, जिनमें इस प्रकार किये गए कार्यकारी तथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे जो उस राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार हों और उनको परिधि के अन्दर आते हों फिर चाहे वे उस राज्य में किये गये हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है, अथवा अन्यत्र किये गये हों। किन्तु स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रति-पूर्ति से भिन्न रूप में), रायस्टियों पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले फीसों अथवा ऐसी ही अन्य अदायगियों के तौर पर अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमिशन अथवा अन्य प्रभारों के तौर पर, अथवा, बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में यदि कोई रकमें अदा की गई हों तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को या उसके अन्य कार्यालयों में

से किसी कार्यालय के स्थायी स्थापन द्वारा रायल्टियों, पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले फीसों अथवा ऐसी ही अन्य अदायगियों के रूप में, की गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में, अथवा, बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके कार्यालयों में से किसी अन्य कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) प्रभारित की गई हो।

4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों में अनुभाजित किये जाने के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए माने जाने वाले लाभों को तय करने की प्रथा रही है, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी प्रथागत अनुभाजन पद्धति से, कर लगने वाले लाभों के निर्धारण से प्रतिबंधित नहीं करेगी; लेकिन अपनाई गई अनुभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

5. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिये माल या पण्य वस्तुएं खरीदी गई हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां आय में लाभों की वे मर्से शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

विमान-परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान-परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, संयुक्त व्यापार अथवा अंतर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध नार्वेजियन, डेनिश तथा स्वीडिश संयुक्त विमान-परिवहन संघ, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस सिस्टम (एस.ए.एस.) द्वारा अर्जित लाभों पर लागू होंगे, किन्तु जहां तक कि वे स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस सिस्टम (एस.ए.एस.) की नार्वेजियन भागीदार कंपनी—डे नास्क

लुफ्तफर्त्सैल्सकैप ए/एस (जी.एन.एल.) द्वारा अर्जित लाभ उक्त संगठन में उसके हिस्से के अनुपात में हों।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिचालन से संबंधित निधियों पर के ब्याज को ऐसे विमान-परिचालन से प्राप्त लाभ माना जाएगा, तथा अनुच्छेद 12 के उपबंध ऐसे ब्याज के मामले में लागू नहीं होंगे।

5. “विमान-परिचालन” पद से तात्पर्य होगा—विमान के मालिकों या पट्टेदारों अथवा अवक्रेताओं द्वारा विमान द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल के परिवहन का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, विमान का आकस्मिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्य-कलाप शामिल है।

अनुच्छेद 9

जहाजरानी

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोत परिवहन से अर्जित आय पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोत परिवहन से अर्जित आय पर उस संविदाकारी राज्य में, जिसमें ऐसा परिचालन किया जा रहा हो, कर लगाया जा सकेगा; किन्तु इस प्रकार लगाया गया कर, उस राज्य के आंतरिक कानून द्वारा अन्यथा लगाए जाने वाले कर के 50% से अधिक नहीं होगा। इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिये, भारत में कर लगाये जाने योग्य ऐसे लाभों की रकम, भारत से यात्रियों अथवा माल को लाने ले जाने से प्राप्त होने वाली रकम के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध किसी पूल, संयुक्त कारोबार अथवा अंतर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

4. किसी उद्यम को दोनों संविदाकारी राज्यों का उद्यम माना जाएगा यदि :—

(क) यदि उद्यम किसी कंपनी या व्यक्तियों के किसी ऐसे अन्य निकाय द्वारा चलाया जाता हो जिसमें सभी भागीदारों का संयुक्त रूप से या पृथकतः दायित्व हो तथा उन भागीदारों में से कम से कम एक भागीदार का असीमिति दायित्व हो; और

(ख) भागीदारों में से कम से कम एक भागीदार संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी हो तथा उन भागीदारों में से एक या अधिक भागीदार दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी हों; और

- (ग) उद्यम का प्रभावी प्रबंध संविदाकारी राज्यों में से केवल किसी एक राज्य में ही नहीं किया जाता हो ।

उस स्थिति में, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अधीन रहते हुए उद्यम के लाभों पर कर उनके लाभों के अंश के अनुपात से उस राज्य में लगाया जाएगा, जहां के उप पैराग्राफ (ख) में उल्लिखित भागीदार निवासी हों । इस पैराग्राफ के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उनका आशय उन भागीदारों को कोई भी लाभ पहुंचाना है जो संविदाकारी राज्यों से भिन्न किसी राज्य के निवासी हों ।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये जलयानों के परिवचालन से प्राप्त आय में, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य वस्तुओं के परिवहन के संबंध में कंटेनरों (जिनमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर तथा अन्य साज-सामान शामिल हैं) के इस्तेमाल, रख-रखाव अथवा किराये से प्राप्त आय शामिल है ।

अनुच्छेद 10

सहयोगी उद्यम

जहां

- (क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं, और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं, जैसी कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु, उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किये जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद 11

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है ।

2. तथापि ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लग सकता है जिस राज्य की लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हित-भागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

(क) लाभांशों की सकल रकम का 15%, यदि हित-भागी स्वामी (भागीदारी से भिन्न) कोई ऐसी कंपनी है, जो लाभांश अदा करने वाली कंपनी की पूंजी की कम से कम 25 प्रतिशत पूंजी पर प्रत्यक्षतः अधिकार रखती हो तथा लाभांश नए अंशदान के कारण माने जाने योग्य हों ;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल रकम का 25 प्रतिशत । यह पैराग्राफ, ऐसे लाभों के मामले में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें से लाभांश अदा किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांशों" पद का अर्थ है शेयरों से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण-बाधे नहीं हों, लाभों में सम्मिलित हों, तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय, जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयर से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिस राज्य की वितरण करने वाली कंपनी निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित आधार से उसमें स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं करता हो, और वह नियंत्रक कंपनी जिसके संबंध में लाभांश अदा किये जाते हैं वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार से प्रभावी रूप से संबंधित हो । ऐसे मामलों में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कंपनी द्वारा अदा किये गये लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगायेगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के निवासी को इस प्रकार के लाभांश अदा नहीं किये जाते अथवा जहां तक कि नियंत्रक कंपनी जिसके संबंध में लाभांश अदा किये जाते हैं, उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन से अथवा किसी निश्चित आधार से प्रभावी रूप से सम्बन्धित नहीं है अथवा कंपनी के अवितरित लाभों पर लगाया जा सकने वाला कर नहीं लगाया जायगा चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों ।

6. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में यथाप्रयुक्त “नया अंश-दान” पद का अर्थ है इस अभिसमय के लागू होने की तारीख के बाद एक संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा जारी किए गए तथा दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा लाभदायक रूप से धारित बोनस शेयरों से भिन्न शेयर-पूंजी ।

अनुच्छेद 12

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें वह अर्जित होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी हो और ब्याज, इस अभिसमय के लागू होने की तारीख के बाद प्रथमतः दिए गए ऋण या उधार के संबंध में अदा किया जाए तो, इस प्रकार प्रभारित कर ब्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैरा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, —

(क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट होगी, बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है;

(i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, राजनैतिक उपमंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक;

(ख) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक कर से छूट तब होगी जब यह ब्याज उपपैराग्राफ (क) में उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न, किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है बशर्ते कि जिस लेन-देन के कारण ऋण-दावा उद्भूत होता है उसे प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा इस संबंध में इस आधार पर अनुमोदित किया गया है कि वह उस राज्य के औद्योगिक विकास के हित में है ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “ब्याज” शब्द से अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त आय, चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं, और खासतौर

पर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय तथा बंधपत्रों या ऋण पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों या ऋण-पत्रों से सम्बद्ध प्रीमियम तथा पुरस्कार शामिल हैं । विलम्ब से की गई अदायगी के लिये दण्डिक-प्रभार को इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिये ब्याज नहीं माना जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने से, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जहां ब्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता हो, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो, तथा जिस ऋण-दावे के संबंध में ब्याज अदा किया जाता हो वह ऐसे स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार से प्रभावी रूप से संबंधित हो । ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 अथवा 15 के उपबंध ही, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उद्भूत हुआ तब माना जायेगा यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य उस राज्य का कोई राजनैतिक उपमंडल, स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन या निश्चित आधार है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की गई है, तथा ऐसा ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार द्वारा वहन किया जाता है, तब ऐसा ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जायेगा जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार स्थित है ।

7. जहां ब्याज अदा करने वाले तथा हित भागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिये ब्याज की रकम अदा की गई है, किसी भी कारण उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिये इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । इस प्रकार के मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक् अनुसरण करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जायेगा ।

अनुच्छेद 13

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गई रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें वे उद्भूत होती हैं। परन्तु जहां तक तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का संबंध है, जहां इस प्रकार की फीस इस अभिसमय के लागू होने की तारीख के बाद हस्ताक्षर की गई संविदा के संबंध में अदा की जाती है वहां इस प्रकार लगाया गया कर इस प्रकार की फीस के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ, यदि इस अभिसमय के लागू होने के पश्चात् नार्थ सेभिन्न किसी दूसरे राज्य के साथ भारतीय कर की निम्न दर लगाने पर सहमति होती है तो वही दर लागू की जाएगी।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से तात्पर्य किसी भी प्रकार की ऐसी अदायगियों से है, जो साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों, जिसमें चलचित्र, फिल्में या रेडियो अथवा दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली फिल्में या टेपें शामिल हैं, कोई पेटेंट द्रव्यमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के किसी भी कॉपीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त हों।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" शब्द से प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के प्रतिफल में, जिसमें तकनीकी अथवा दूसरे कामियों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, अदायगियां करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को की गई अदायगियों सेभिन्न किसी व्यक्ति को की गई किसी भी रकम की अदायगियां अभिप्रेत हैं।

5. पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियां तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, उसमें स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ निष्पादित करता है, तथा यह अधिकार, संपत्ति अथवा संविदा, जिसके संबंध में रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत हुई मानी जाएगी, यदि अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उपमंडल,

कोई स्थायी प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहां रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की देनदारी उत्पन्न हुई हो, तथा ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है तब ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अदा करने वाले तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच विशिष्ट संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए अदा की गई फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जो ऐसे संबंधों के नहीं होने की स्थिति में अदा की गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का अतिरिक्त भाग, इस अभिसमय के दूसरे उपबंधों का उचित ध्यान रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाये जाने योग्य रहेगा।

अनुच्छेद 14

पूँजीगत अभिलाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. चल संपत्ति के अंतरण से हुए अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के स्थायी संस्थापन की व्यापारिक संपत्ति के भाग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित चल संपत्ति हो, जिनमें ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा संपूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति (जिसमें कन्टेनर्स तथा संबंधित उपस्कर शामिल हैं) के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अंतरणकर्ता निवासी है।

4. किसी ऐसी कंपनी की पूंजी स्टॉक के हिस्सों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी संपत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अथवा संपत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. किसी ऐसी कंपनी के, पैराग्राफ 4 में उल्लिखित हिस्सों से भिन्न हिस्सों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी भी संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. किसी व्यक्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी स्वरूप के दूसरे क्रियाकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो; उस मामले में, उस दूसरे राज्य में उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि उसकी दूसरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की अवधि अथवा अवधियां आय के किन्हीं लगातार दो वर्षों में कुल 183 दिन अथवा उससे अधिक हो तो; उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में निष्पादित उसके कार्यकलापों से प्राप्त होती हो।

तथापि, जिस सीमा तक ऊपर उल्लिखित पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर नहीं लगाया जाता है, जहां का प्राप्त करने वाला निवासी है तो पारिश्रमिक पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेष रूप से स्वतन्त्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी क्रियाकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त चिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतंत्र क्रियाकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 16

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं हो। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उसमें प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमो-लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) यदि प्राप्तकर्ता किन्हीं दो लगातार आय वर्षों में कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो; तथा

(ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो उस राज्य का निवासी है जिसका कि पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला निवासी है; तथा

(ग) पारिश्रमिक, किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से, तर्कसंगत रूप से संबंधित नहीं है जो नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा हवाई जहाजों के परिचालन के संबंध में किये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर उसी राज्य में लगाया जा सकेगा। जहां नावों का कोई निवासी स्कैन्डिनेवियन एयरलाइंस सिस्टम (एम. ए. एस.) कन्सोर्टियम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में हवाई जहाज के परिचालन में किये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर कर केवल नावों में ही लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 17

निदेशकों की फीम तथा उच्च स्तरीय

प्रबन्धकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा निदेशक मंडल के सदस्य की हैमियत से अथवा किसी कंपनी के वैसे ही संगठन में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीम तथा उसी प्रकार की अशायतियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

2 एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी ऐसी कंपनी के जो दूसरे राज्य की निवासी है, उच्च स्तरीय प्रबंधकीय पद पर नियुक्त कर्मचारी की हैसियत में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 18

मनोरंजनकर्त्ताओं तथा खिलाड़ियों द्वारा अर्जित आय

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्त्ता के रूप में, जैसे कि थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा संगीतकार अथवा खिलाड़ी के रूप में अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों में, जिन्हें वह दूसरे संविदाकारी राज्य में सम्पन्न करता है, प्राप्त आय पर कर उस दूसरे राज्य में लग सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा इस प्रकार संपन्न अपने व्यक्तिगत क्रियाकलापों के संबंध में आय स्वयं मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है अपितु अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहां अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी उस आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिस में मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे क्रियाकलाप किये जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, पैराग्राफ 1 में यथा पारिभाषित ऐसे कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी जिसमें ऐसे कार्यकलाप किये जाते हैं यदि मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी का दौरा दो संविदाकारी राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अंतर्गत आता हो अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की, जिसमें राजनैतिक उपमंडल अथवा उस दूसरे राज्य के स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सार्वजनिक निधियों से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से समर्थित हो।

अनुच्छेद 19

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उपमंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके उपमंडल अथवा प्राधिकरण के लिए सरकारी स्वरूप के कार्यों के रूप में की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त पेंशन से भिन्न, पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा।

(ख) लेकिन ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हैं तथा व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो :

(i) उस राज्य का राष्ट्रिक है ; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बना था।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उपमंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित कोष में से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उपमंडल अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा।

(ख) लेकिन ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल तब लग सकेगा यदि :

(i) व्यक्ति उस दूसरे राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो, अथवा

(ii) ऐसी पेंशन पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त हो।

3. अनुच्छेद 16, 17 तथा 20 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपमंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किये गये कार-बार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 20

गैर-सरकारी पेंशन, वार्षिक तथा निर्वाह-धन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्त्रोतों से प्राप्त किसी पेंशन पर जो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न हो, अथवा किसी वार्षिकी पर कर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. "पेंशन" शब्द में पिछली सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुए जख्मों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली आवधिक अदायगी अभिप्रेत है।

3. "वार्षिकी" शब्द से जीवन काल में अथवा विनिश्चित या निश्चय समयावधि के दौरान रुपयों अथवा उसके बराबर द्रव्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल की अदायगी करने के इकरार के अंतर्गत निश्चित समय में समय-समय पर अदायगी योग्य निश्चित राशि अभिप्रेत है।

4. नार्वे के किसी निवासी द्वारा प्राप्त तथा भारतीय निवासी द्वारा प्रदत्त निर्वाह धन पर नार्वे में उस सीमा तक कर से छूट होगी जहां तक कि ऐसी अदायगीया भारतीय कर के प्रयोजनार्थ कटौती योग्य नहीं होती है।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगीया

1. ऐसी अदायगीयां पर, जो एक विद्यार्थी अथवा व्यवसायी प्रशिक्षु एक संविदाकारी राज्य में आने से तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और

जो प्रथमोलिखित राज्य में केवल अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ मौजूद रहता है, अपने निर्वाह, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए प्राप्त करता है, उस राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य में बाहर के स्रोतों के उद्भूत होती हों।

2. इसके अतिरिक्त ऐसे अनुदानों, छात्रवृत्तियों तथा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत नहीं आने वाले नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में, पैराग्राफ 1 में वर्णित विद्यार्थी अथवा व्यवसायी प्रशिक्षु ऐसी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के दौरान उन्हीं छूटों, राहतों अथवा घटौतियों का हकदार होगा जो उस राज्य के निवासी को करों के संबंध में उपलब्ध हैं जिसका वह दौरा कर रहा है।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की उन मदों पर कर जहां कहीं उद्भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथार्थानुगत अचल संपत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में, वहां स्थित किसी निश्चित स्थान में, स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा संपत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 23

अपतटीय कार्यकलाप

1. इस अभिसमय के किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी इस अनुच्छेद के उपबंधों का प्रभाव होगा।

2. कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में समुद्रतल तथा अवमुखा तथा उस दूसरे राज्य में स्थित उनके प्राकृतिक संसाधनों की

खोज अथवा शोषण के सिलसिले में अपतटीय कार्यकलाप करता है, तो ऐसे कार्यकलापों को, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 और 4 के अधीन रहते हुए, उन कार्यकलापों जैसा समझा जाए जो उस दूसरे राज्य में वहां स्थित स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के माध्यम से कारोबार करने के संबंध में किये जाते हैं।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंध ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे जो किसी भी 12 महीने की अवधि में कुल मिलाकर 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए किये जाते हैं। तथापि, इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ :

(क) ऐसे उद्यम द्वारा किये गये कार्यलाप जो दूसरे उद्यम से सम्बद्ध हैं, उस उद्यम यम द्वारा किये गये समझे जाएंगे जिसके साथ वह सम्बद्ध है यदि सम्बन्धित कार्यकलाप तत्त्वतः वैसे ही हों जैसे कि अन्त में उल्लिखित उद्यम द्वारा किये जाते हैं;

(ख) दो उद्यमों को आपस में सम्बद्ध माना जाएगा यदि उनमें से एक को दूसरे उद्यम द्वारा 'प्रत्यक्षतः' या अप्रत्यक्षतः नियंत्रित किया जाता है अथवा दोनों को किसी तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः नियंत्रित किया जाता है।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी स्थान को, अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच सामान अथवा कामिकों को लाने ले जाने से, जहां किसी संविदाकारी राज्य में समुद्रतल तथा अवमुखा तथा उनके प्राकृतिक संसाधन की खोज तथा शोषण के सिलसिले में कार्यकलाप किये जाते हैं, अथवा ऐसे कार्यकलापों में कर्षनाथ तथा दूसरे सहायक पोतों के प्रचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है।

इस पैराग्राफ के उपबंधों के होने हुए भी, ऐसे प्रचालन से प्राप्त लाभों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसा कार्य किया जाता है; परन्तु इस प्रकार लगाया गया कर उस राज्य के अपने कानून द्वारा अन्यथा लगाये गये कर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ ऐसे लाभों की वह राशि जिस पर भारत में कर लगाया जाना है प्राप्त की जा सके योग्य रकम के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। फिर भी, यदि इस अभिसमय के लागू होने की तारीख के बाद नार्वे से भिन्न किसी दूसरे देश के साथ, भारतीय कर की कोई नीची दर स्वीकार की जाती है तो उस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार की दर लागू की जाएगी।

5. (क) इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (ख) के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित समुद्रतल तथा अवमुखा

और उनके प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा शोषण से संबंधित किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त आय कर, उस दूसरे राज्य में किये गये अपतटीय कार्यों की सीमा तक, कर केवल उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा बशर्ते कि अपतटीय नियोजन किसी भी 12 महीने की अवधि में कुल मिलाकर 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए किया जाता है।

(ख) किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा ऐसे स्थान को या स्थानों के बीच, जहां किसी संविदाकारी राज्य में समुद्रतल तथा अधमृदा और उनके प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा शोषण से संबंधित कार्यकलाप किये जा रहे हों, माल अथवा कामिको को लाने ले जाने में लगाये गये जलयान अथवा हवाई जहाज किये गये नियोजन के संबंध में अथवा कर्षनाव अथवा इस प्रकार के कार्यकलापों की सहाय-नार्थ प्रचालित दूसरे जलपत्तों पर किये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा उसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 24

पूँजी

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल संपत्ति द्वारा निरूपित पूँजी पर, जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी के स्वामित्व में हो तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल संपत्ति द्वारा निरूपित पूँजी पर जो किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक संपत्ति के अंग के रूप में एक संविदाकारी राज्य के उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अंतर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलपोतों और वायुयानों द्वारा और ऐसे जलपोतों और वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति (जिसमें आधान तथा संबंधित उपकरण शामिल हैं) द्वारा निरूपित पूँजी पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगाया जा सकेगा जिसका ऐसे जलपोतों वायुयानों अथवा संपत्ति का स्वामी निवासी है।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूँजी के अन्य सभी तत्वों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 25

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में, आय और पूँजी के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे जब तक कि इस अभिसमय में उनके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जाता है।

2. जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूँजी का स्वामित्व रखता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार नार्वे में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की आय पर उस रकम के बराबर कर से कटौती के रूप में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती द्वारा छूट देगा जो नार्वे में अदा किए गए आय कर की रकम के बराबर होगी; और उस निवासी की पूँजी पर कर से कटौती के रूप में उतनी छूट प्राप्त होगी जो नार्वे में अदा किए गए पूँजी-कर की रकम के बराबर हो। तथापि, दोनों मामलों में ऐसी कटौती (कटौती देने से पूर्व यथा संगणित) आयकर अथवा पूँजी-कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय और पूँजी, जैसा भी मामला हो, के कारण उत्पन्न हुआ माना जा सकता हो जिस पर नार्वे में कर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जहां ऐसा निवासी कोई ऐसी कंपनी है, जिसके द्वारा भारत में अतिकर देय है, वहां नार्वे में अदा किए गए आय कर के बारे में कटौती पहले तो कंपनी द्वारा भारत में देय आयकर से की जाएगी और शेष के लिए, यदि कोई हो, भारत में उसके द्वारा देय अतिकर से कटौती की अनुमति दी जाएगी।

3. जहां नार्वे का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूँजी का स्वामित्व रखता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां नार्वे पैराग्राफ 4, 5, 6 और 7 के उपबंधों के अधीन रहने हुए इस प्रकार की आय तथा पूँजी पर कर से छूट प्रदान करेगा।

4. जहां नार्वे का कोई निवासी आय की ऐसी मदें प्राप्त करता है, जिन पर अनुच्छेद 9, 11, 12, 13, 14 पैरा 5, 17, 22 और 23 के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां नार्वे उस व्यक्ति की आय पर, भारत में अदा किए गए कर के बराबर की रकम की दर से कटौती की अनुमति देगा। लेकिन, ऐसी कटौती कटौती करने से पूर्व यथा संगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो भारत में प्राप्त आय की ऐसी मदों से प्राप्त की गई मानी जा सकती हो।

5. पैराग्राफ 5 में उल्लिखित कटौती के प्रयोजनार्थ "भारत में अदा किया गया आयकर" पद में भारत के कानूनों के अन्तर्गत और इस अभिसमय के अनुसार, निम्न-लिखित के अन्तर्गत उस वर्ष के लिये मंजूर की गई कर की

किसी छूट अथवा कटौती को छोड़कर ऐसी कोई भी रकम शामिल हुई मानी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में देय रही हो :

(क) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10(4), 10(4क), 10(4ख), 10(6) (VIIक), 10(16) (IV) और 80ड, जहाँ तक कि वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख को लागू थीं और तब से उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है अथवा उनमें इतना कम संशोधन किया गया है कि उसमें उनके समान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, अथवा

(ख) कोई भी अन्य उपबंध जो कर योग्य आय अथवा कर से किसी छूट अथवा घटौती की संगणना करने में कटौती संजूर करने हुए 11 नवम्बर, 1983 के बाद अधिनियमित किया गया हो जिसको संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी भारत के आर्थिक विकास के प्रयोजन के लिए होना मानते हों, यदि उसमें उसके बाव्य संशोधन नहीं किया गया हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन किया गया हो जिससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

यह पैराग्राफ अनुच्छेद 17 पर लागू नहीं होता है।

6. पैराग्राफ 4 में दर्शाई गई कटौती के लिए, ब्याज पर भारतीय कर को इस दर से अदा किया गया समझा जाएगा कि वह 15 प्रतिशत की दर से कम नहीं है।

7. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5 और 6 के उपबंध उस अवधि के पहले 10 वर्षों के लिए लागू होंगे जिसके लिये यह अभिसमय प्रभावी रहेगा परन्तु संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए एक दूसरे के साथ परामर्श कर सकते हैं कि क्या इस अवधि को बढ़ाया जायगा।

8. इस अभिसमय के अन्तर्गत जहाँ एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में प्राप्त आय अथवा अपनी पूँजी के बारे में उस संविदाकारी राज्य से कर से छूट मिलती है, तो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य उस व्यक्ति की बाकी आय अथवा पूँजी पर कर की गणना करने में, कर की वह दर लागू कर सकता है जो उस स्थिति में लागू करने योग्य होती यदि इस अभिसमय के अनुसार छूट-प्राप्त आय अथवा पूँजी पर उस प्रकार कोई छूट प्राप्त नहीं हुई हो।

अनुच्छेद 26

सम व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो इस कराधान और संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो जो उस

दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है। यह उपबंध अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी, ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. राष्ट्रिकताहीन व्यक्तियों पर जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी हैं दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के वैसी ही परिस्थितियों में और वैसी ही शर्तों के अधीन वैसे ही कार्य में प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों।

4. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य ऐसे व्यक्तियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छूटें, राहतें, घटौतियाँ और कटौतियाँ प्रदान करने को बाध्य होगा जो कानूनन केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, जो वहाँ के निवासी हैं।

5. जिन मामलों में अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं उन्हें छोड़कर एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टियाँ और अन्य वितरण ऐसे उद्यम के कर लगने योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती पाने योग्य होंगे जैसे कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के निवासी को अदा किए गए थे। इसी प्रकार, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिए गए कोई भी ऋण, ऐसे उद्यम की कर लगने योग्य पूँजी के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती पाने योग्य होंगे, जैसे कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के निवासी को अनुबंधित किए गए थे।

6. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूँजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर वैसी ही परिस्थितियों में और वैसी ही शर्तों के अधीन लागू है अथवा हो सकती है।

7. इस अनुच्छेद के उपबन्धों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के उन राष्ट्रियों को जो प्रथम संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक नहीं हैं, इस संविदाकारी राज्य के स्वदेश लौटने वाले राष्ट्रियों को दी जाने वाली असाधारण कर राहत देने को बाध्य होगा।

अनुच्छेद 27

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन राज्यों के आन्तरिक कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों के होते हुए भी, अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवासी है, अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 26 के पैराग्राफ (1) के अन्तर्गत आता है, तो वह अपना मामला उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण उस पर ऐसा कर लगा है जो इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किये गये किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक समझौते से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अन्तर्गत के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिसकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। समझौते पर पहुंचने के लिये जब विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसा आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद 28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का (जिसमें दस्तावेज भी शामिल हैं) आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबन्धों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों के संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस अभिसमय के अन्तर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसी करों की जालसाजी अथवा अपवंचन को रोकने के लिए अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबन्धित नहीं है। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन, यदि सूचना को सूचना भेजने वाले राज्य में मूल रूप से गुप्त समझा जाता है तो, उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट किया जाएगा, जो उन करों के निर्धारण अथवा वसूली, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में अन्तर्गस्त हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों के संबंध में संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा, जिसमें, जहां कहीं उपयुक्त हो, कर अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :—

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना देना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं;
- (ग) ऐसी सूचना देना, जिसमें कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद 29

वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के अंतर्गत आने वाले ऐसे करों की वसूली में एक-दूसरे की मदद करते और समर्थन देने का जिम्मा लेते हैं जो अनुरोधकर्ता राज्य में वसूल न किए जा सकते हों।

2. दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य के करों से संबंधित ऐसे दावों की वसूली में सहायता के लिए किए गए अनुरोध को, जो उस राज्य में वसूल न किए जा सकते हों, प्रवर्तन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वीकार किया जाएगा और कर के ऐसे दावों को, उस दूसरे राज्य के अपने करों के प्रवर्तन और उगाही के लिए लागू कानूनों और प्रशासनिक कार्यविधि के अनुसार, वसूल किया जाएगा।

3. किसी कर के दावे की वसूली में सहायता के लिए किए गये अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे :

- (क) इस आशय का एक घोषणा-पत्र कि कर का दावा अभिसमय के अंतर्गत आने वाले किसी कर से संबंधित है और यह कि इसकी वसूली नहीं की जा सकती;
- (ख) जिस राज्य ने अनुरोध किया है उसमें लागू करने की अनुमति संबंधी दस्तावेज की एक अधिकारिक प्रति;
- (ग) वसूली के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज; और
- (घ) जहां उचित समझा जाय, वहां प्रशासनिक निकाय अथवा न्यायालय के किसी भी संगत फैसले की एक प्रमाणित प्रति।

4. भारतीय कर के मामले में, अनुरोध केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा नावों राज्य की सरकार को भेजा जाएगा और नावों के कर के मामले में अनुरोध वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, राजस्व विभाग को भेजा जाएगा।

5. जहां कर का दावा उस संबंध में अपील किये जाने अथवा किसी अन्य कार्यवाही के कारण निर्णायक नहीं बना हो, वहां एक संविदाकारी राज्य अपने राजस्व को बचाने के लिए, दूसरे संविदाकारी राज्य से ऐसे अन्तरिम उपाय करने का अनुरोध कर सकता है जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत वैध हों।

6. किसी करदाता से प्राप्य करों की वसूली में सहायता के लिए अनुरोध तभी किया जाएगा जब अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में उस करदाता से कर वसूल करने के लिए उसकी पर्याप्त परिसंपत्ति उपलब्ध नहीं हो।

7. जिस संविदाकारी राज्य में इस अनुच्छेद के पैरा-ग्राफ 1, 2 और 5 के अनुसरण में कर वसूल किया जाता है, वह इस प्रकार वसूल की गई रकम तत्पश्चात् गुरुरत हमारे संविदाकारी राज्य को भेजेगा।

अनुच्छेद 30

राजनयिक और कॉमिनी अधिकारी

इस अभिसमय की किसी भी बात से राजनयिक अथवा कॉमिनी अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त विस्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 31

प्रवर्तन

1. दोनों संविदाकारी राज्य, इस अभिसमय को लागू करने के लिए अपनी-अपनी विधि द्वारा अपेक्षित कार्यविधि विधियों के पूरा किए जाने के बारे में हमारे राज्य को अधिसूचित करेंगे। यह अभिसमय उस वर्ष से लागू होगा जिस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे और तदनन्तर;

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में अभिसमय पर हस्ताक्षर किये गए हैं उस वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले पिछले वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;

(ख) नावों में, जिस कैलेंडर वर्ष में अभिसमय पर हस्ताक्षर किये गये हैं उस वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष में (जिस में ऐसी किसी वर्ष में आरम्भ होने वाली लेखा अवधियां शामिल हैं, से संबंधित) आय अथवा पूंजी पर करों के संबंध में; लागू होगा।

2. आय के दोहरे कराधान के परिहार के लिए नावों सरकार तथा भारत सरकार के बीच हुआ करार, जिस पर 20 जुलाई, 1959 को हस्ताक्षर किए गए थे, आय पर उन करों के संबंध में समाप्त हो जाएगा और नहीं रहेगा जिस पर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबंधों के अनुसार वर्तमान करार लागू होता है।

अनुच्छेद 32

समाप्ति

यह अभिसमय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति

के बाद से शुरू होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष में जून के तीसरे दिन को या उससे पहले, राजनयिक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को, समाप्ति कर लिखित नोटिस दे सकेगा। ऐसी स्थिति में, यह अभिसमय—

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, उसके अगले परवर्तित वर्ष में अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वर्ष में प्राप्त आय के बारे में और जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी राजस्व वर्ष की समाप्ति पर धारित पूंजी के संबंध में;

(ख) नावों में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उस वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष (जिसमें ऐसे वर्ष में आरम्भ होने वाली लेखा अवधियां शामिल हैं) से संबंधित आय पर अथवा पूंजी पर करों के संबंध में,

निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ छियासी के दिसम्बर माह के इकतीसवें दिन को, हिन्दी, नावेंजियन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया, इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इन पाठों में से किसी के भी बीच भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

नावें राज्य की सरकार
की ओर से

ह०/-
चांद कृष्ण तिव्कू

ह०/-
करे दहलेन

प्रोटोकोल

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के अपवचन को रोकने के लिए नावें राज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच आज इस अभी समय पर हस्ताक्षर करते समय, अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हो गए हैं जो इस अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे;

1. अनुच्छेद 16 के बारे में।

जहां कोई उद्यम, जो अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा हवाई जहाजों के प्रचालन में लगा है, किसी ऐसी असीमित भागीदारी द्वारा चलाया जाता है, जिसका एक अथवा एक से अधिक भागीदार एक संविदाकारी राज्य के

निवासी हैं और एक अथवा एक से अधिक भागीदारी दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी हैं, और संविदाकारी राज्यों के सहमत प्राधिकारी इस समझौते पर नहीं पहुंच सकते कि उद्यम की प्रभावी प्रबंध व्यवस्था संविदाकारी राज्यों में से किस राज्य में स्थित है, वहां अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 3 में वर्णित पारिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका प्राप्तकर्ता निवासी है।

2. अनुच्छेद 25 के बारे में।

संविदाकारी राज्य सहमत हैं कि अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 3 और 4 के स्थान पर, नावों के अनुरोध पर, जिसे राजनयिक माध्यमों से एक टिप्पणी द्वारा भेजा जाएगा निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा, जो उस टिप्पणी की राजनयिक माध्यमों से प्राप्ति की पुष्टि पर 30वें दिन लागू होगा और उस कैलेंडर वर्ष (जिसमें ऐसे वर्ष में आरम्भ होने वाली लेखा अवधियां शामिल हैं) के अगले परवर्ती वर्ष के संबंध में, जिसमें टिप्पणों का आदान-प्रदान किया गया है, आय अथवा पूंजी पर करों के संबंध में पहली बार लागू होगा ;

“3 और 4 :

जहां नावों का कोई निवासी इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार आय प्राप्त करता है अथवा पूंजी का स्वामित्व रखता है, जिन पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां नावें उस व्यक्ति के आय-कर अथवा पूंजी कर में से, भारत में अदा किए गए कर के बराबर की रकम, कटौती के रूप में मंजूर करेगा। परन्तु इस प्रकार की कटौती, कटौती देने से पूर्व यथा संगणित नावों के कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो भारत में प्राप्त आय अथवा स्वामित्व की पूंजी को देखते हुए उचित हो।”

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने, इस प्रोटोकल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में 1986 के दिसम्बर मास के इकतीसवें दिन दो प्रतियों में हिन्दी, नावों की और अंग्रेजी भाषाओं में किया गया, सभी पाठ समानतः प्रामाणिक होंगे। इन पाठों में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

नावें राज्य की सरकार
की ओर से

ह०/-
चांद कृष्ण तिव्कू

ह०/-
करे दहलेन

[फा.सं. 505/3क/81-एफ टी डी]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 9th September, 1987

NOTIFICATION NO. 7514

INCOME TAX

G.S.R. 756(E).—Whereas the annexed Convention between the Republic of India and the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital has entered into force in the year one thousand nine hundred and eighty-six, being the year in which it was signed, on the notification by both the contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws, as required by paragraph 1 of Article 31 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

CONVENTION

Between

THE REPUBLIC OF INDIA

and

THE KINGDOM OF NORWAY
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Norway desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows:

ARTICLE 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular :

(a) In India :

- (i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964);
- (iii) the Wealth-tax imposed under the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(hereinafter referred to as "Indian tax").

(b) In Norway :

- (i) the national tax on income (inntektsskatt til staten);
- (ii) the county municipal tax in income (inntektsskatt til fylkeskommunen);
- (iii) the municipal tax on income (inntektsskatt til kommunen);
- (iv) the national contributions to the Tax Equalisation Fund (fellesskatt til Skattefordelingsfondet);
- (v) the national tax on capital (formuesskatt til staten);
- (vi) the municipal tax on capital (formuesskatt til kommunen);
- (vii) the national tax relating to income and capital from the exploration for and the exploitation of submarine petroleum resources and activities and work relating thereto, including pipeline transport of petroleum produced (skatt til staten vedrørende inntekt og formue i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøske petroleumforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder røedningstransport av utvunnet petroleum);
- (viii) the national dues on remuneration to non-resident artistes (avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet);
- (ix) the seamen's tax (sjømannsskatt);

(hereinafter referred to as "Norwegian tax").

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3

General definitions

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes territorial sea and the air space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law.
- (b) the term "Norway" means the Kingdom of Norway, including any area outside the territorial waters of the Kingdom of Norway where the Kingdom of Norway, according to Norwegian legislation and in accordance with international law, may exercise her rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources; the term does not comprise Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependencies outside Europe;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Norway as the context requires;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Norwegian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (e) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Norway, the Minister of Finance and Customs or his authorised representative;

(i) the term "nationals" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

ARTICLE 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
- (i) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
- (j) an installation or structure used for the exploration of natural resources;
- (k) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than three months together with other such sites, projects or activities, if any;
- (l) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than six months within any 12-month period.

3. Notwithstanding the preceeding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise

solely for the purpose of processing by another enterprise;

- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for other activities which have a preparatory or auxiliary character, for enterprise.

However, the provisions of sub-paragraphs (a) to (e) shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purposes other than the purposes specified in the said sub-paragraphs.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if :—

- (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control as, that enterprises.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprise controlling, controlled by, or subject to the same common control as, that enterprise, he shall not be considered as an agent of an independent status within the meaning of this paragraph if it is shown that the transactions between the agent and the enterprise were not made under arm's-length conditions. In that case the provisions of paragraph 4 shall apply.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to :

- (a) that permanent establishment;
- (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or
- (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of the other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprises, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

Air transport

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply to profits derived by the joint Norwegian, Danish and Swedish air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), but only in so far as profits derived by Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL), the Norwegian partner of the Scandinavian Airlines System (SAS), are in proportion to its share in that organisation.

4. For the purposes of this article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of article 12 shall not apply in relation to such interest.

5. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

ARTICLE 9

Shipping

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 profits derived from the operation of ships in international traffic may be taxed in the Contracting State in which such operation is carried on; but the tax so charged shall not exceed 50 per cent of the tax otherwise imposed by the internal law of that State. For purposes of this paragraph, the amount of such profits subject to tax in India shall not exceed 7.5 per cent of the sums receivable in respect of the carriage of passengers or freight embarked in India.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, in a joint business or in an international operating agency.

4. An enterprise shall be deemed to be an enterprise of both Contracting States if :

- (a) the enterprise is carried on by a company or any other body of persons where all the partners are jointly and severally liable and at least one of the partners has unlimited liability; and
- (b) at least one of the partners is a resident of one of the Contracting States and one or more of them is a resident of the other Contracting State; and
- (c) the effective management of the enterprise is not carried on solely in one of the Contracting States.

In that case the profits of the enterprise, subject to paragraph 2 of this article, shall be taxable in the State where partners mentioned in sub-paragraph (b) are residents in proportion to their part of the profits. The provisions of this paragraph shall not be construed as to grant any benefits to partners resident of a State other than the Contracting States.

5. For the purposes of this article, income from the operation of ships includes income derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

ARTICLE 10

Associated enterprises

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 11

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial

owner of the dividends the tax so charged shall not exceed :

(a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends and the dividends are attributable to a new contribution;

(b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. As used in paragraph 2 of this article the term "new contribution" means share capital, other than bonus shares, issued after the date of entry into force of this Convention by a company which is a resident of a Contracting State, and beneficially owned by a resident of the other Contracting State.

ARTICLE 12

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according of the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest and it is paid in respect of a loan or debt first created after the date of entry into force of this Convention, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,—

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

(i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person other than a person referred to in sub-paragraph (a) who is a resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State to be in the interest of the industrial development of that State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest

shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13

Royalties and fees for technical services

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State. But insofar as fees for technical services are considered, to the extent such fees are paid in respect of a contract which is signed after the date of entry into force of this Convention, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of such fees. For the purposes of this paragraph, if a lower rate of Indian tax is agreed upon with any other state than Norway after the entry into force of this Convention such rate shall be applied.

3. The term "royalties" as used in this article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or perform in that other State independent personal services from a fixed base

situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 15, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other persons, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 14

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (along or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property (including containers and related equipment) pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that state.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in the preceding paragraphs shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 15

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of Professional services or other activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any two consecutive years of income; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

However, to the extent the above mentioned remuneration is not taxed in the State where the recipient is a resident, the remuneration may be taxed in the other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 16

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any two consecutive years of income; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is a resident of the State of which the recipient is a resident; and
- (c) the remuneration is not reasonably connected with the activities of a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Norway derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the Scandinavian Airlines System (SAS) consortium, such remuneration shall be taxable only in Norway.

ARTICLE 17

Directors' fees and remuneration of top level managerial officials

1. Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or of a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 18

Income earned by entertainers and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived from such activities as defined in paragraph 1 shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are performed if the visit of the entertainer or athlete is

within the framework of cultural exchange between the two Contracting States, or is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the other Contracting State, including a political sub-division or local authority of that other State.

ARTICLE

Remuneration and Pensions in respect of Government Service

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if :

- (i) the individual is a resident of, and a national of that other State; or
- (ii) such pension is exempt from tax in the first-mentioned State.

3. The provisions of Articles 16, 17 and 20 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

ARTICLE 20

Non-Government pensions annuities and alimony

1. Any pensions, other than a pension referred to in article 19, or any annuity derived by a resident of Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

4. Alimony received by a resident of Norway and paid by a resident of India shall be exempt from tax in Norway to the extent such payments are not deductible for the purposes of Indian tax.

ARTICLE 21

Payments received by students and apprentices

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1, a student or business apprentice described in paragraph 1 shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.

ARTICLE 22

Other income

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Convention, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Convention, and arising in the other Convention, State may also be taxed in that other State.

ARTICLE 23

Offshore activities

1. The provisions of this Article have effect notwithstanding any other provision of this Convention.

2. A person who is a resident of a Contracting State and carries on activities offshore in the other Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the seabed and subsoil and their natural resources situated in that other State shall, subject to paragraphs 3 and 4 of this Article, be deemed in relation to those activities to be carrying on business in that other State through a permanent establishment or fixed base situated therein.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply where the activities are carried on for a period not exceeding 30 days in the aggregate in any 12 months period. However, for the purposes of this paragraph:

- (a) activities carried on by an enterprise associated with another enterprise shall be regarded as carried on by the enterprise with which it is associated if the activities in question are substantially the same as those carried on by the last-mentioned enterprise;
- (b) two enterprises shall be deemed to be associated if one is controlled directly or indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by a third person or persons.

4. Profits derived by a resident of a Contracting State from the transportation of supplies or personnel to a location, or between locations, where activities in connection with the exploration or exploitation of the seabed and subsoil and their natural resources are being carried on in a Contracting State, or from the operation of tugboats and other vessels auxiliary to such activities, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Notwithstanding the provisions of this paragraph profits derived from such operation may also be taxed in the Contracting State in which the operation is carried on; but the tax so charged shall not exceed 50 per cent of the tax otherwise imposed by the internal law of that State. For purposes of this paragraph, the amount of such profits subject to tax in India shall not exceed 7.5 per cent of the sums receivable. However if a lower rate of Indian tax is agreed upon with any other state than Norway after the entry into force of this Convention such rate shall be applied for the purposes of this paragraph.

5. (a) Subject to sub-paragraph (b) of this paragraph, salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with the exploration or exploitation of the seabed and subsoil and their natural resources situated in the other Contracting State shall, to the extent that the duties are performed offshore in that other State, be taxable only in that other State

provided that the employment offshore is carried on for a period exceeding 30 days in the aggregate in any 12 months period.

(b) Salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft engaged in the transportation of supplies or personnel to a location, or between locations, where activities connected with the exploration or exploitation of the seabed and subsoil and their natural resources are being carried on in a Contracting State, or in respect of an employment exercised aboard tugboats or other vessels operated auxiliary to such activities, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

ARTICLE 24

Capital

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by movable property (including containers and related equipment) pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the owner of such ships, aircraft or property is a resident.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 25

Elimination of double taxation

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income and capital in the respective Contracting States except where express provision to the contrary is made in this Convention.

2. Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Norway, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income-tax paid in Norway, whether directly or by deduction; and as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in Norway. Such deduction in either case

shall not, however, exceed that part of the income-tax or capital tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Norway. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income tax paid in Norway shall be allowed in the first instance from income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.

3. Where a resident of Norway derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of the Convention, may be taxed in India, Norway shall, subject to the provisions of paragraphs 4, 5, 6 and 7, exempt such income or capital from tax.

4. Where a resident of Norway derives items of income which, in accordance with the provisions of Articles 9, 11, 12, 13, 14 paragraph 5, 17, 22 and 23 may be taxed in India, Norway shall allow as a deduction from the tax on the income of that person an amount equal to the tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income derived from India.

5. For the purposes of the deduction referred to in paragraph 4, the term "income tax paid in India" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax under the law of India and in accordance with this Convention for any year but for an exemption from, or reduction of, tax granted for that year under :—

- (a) sections 10(4), 10(4A), 10(4B), 10(6)(viiia), 10(15)(iv) and 80-L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character ; or
- (b) any other provisions which may be enacted after 11 November, 1983 granting a deduction in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of the economic development of India, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to effect its general character.

This paragraph does not apply to Article 17.

6. For the deduction indicated in paragraph 4, Indian tax on interest shall be considered as having been paid at a rate of not less than 15 per cent.

7. The provisions of paragraphs 5 and 6 of this Article shall apply for the first 10 years for which this Convention is effective but the competent authorities of the Contracting States may consult each other to determine whether this period shall be extended.

8. Where under this Convention a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived or capital owned in the other Contracting State, then the first-mentioned Contracting State may, in calculating tax on the remaining income or capital of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the income or capital exempted from tax in accordance with this Convention had not been so exempted.

ARTICLE 26

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.

4. Nothing containing in this article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

5. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 12 or paragraph 7 of Article 13 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

6. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is

other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

7. The provisions of this Article shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to nationals of the other Contracting State not being nationals of the first Contracting State any exceptional tax relief accorded to repatriating nationals of this Contracting State.

ARTICLE 27

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article 26, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting State.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of options, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 28

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered

by the Convention, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by article 1. And information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 29

Assistance in collection

1. The Contracting States undertake to lend assistance and support to each other in the collection for taxes covered by this Convention which may no longer be contested in the State making the request.

2. A request for assistance in the recovery of tax claims of either of the Contracting States which may no longer be contested in that State will be accepted for enforcement by the other Contracting State and such tax claims shall be recovered in accordance with the laws and administrative practice applicable to the enforcement and collection of its own taxes.

3. The request for assistance in the recovery of a tax claim shall be accompanied ;

- (a) by a declaration that the tax claim concerns a tax covered by the Convention and that it may no longer be contested.

- (b) by an official copy of the instrument permitting enforcement in the State making the request,
- (c) by any other document required for recovery, and
- (d) where appropriate by a certified copy for any relevant decision of the administrative body or a court for law.

4. In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes, Department of revenue to the Ministry of Finance, Government of the Kingdom of Norway, and, in the case of Norwegian tax, the request will be sent by the Ministry of Finance to the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, in India.

5. Where the tax claim has not become final by reason of being subject to appeal or any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such interim measures as are lawful under the laws of that other Contracting State.

6. A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate assets of that tax-payer are not available for recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.

7. The Contracting State in which tax is recovered in pursuance of paragraphs 1, 2 and 5 of this article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the other Contracting State.

ARTICLE 30

Diplomatic and consular officials

Nothing in this Convention shall affect the fiscal absence of such relationship, the provisions of this privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 31

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force in the year in which it is signed and shall thereupon have effect.

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention is signed;
- (b) in Norway, in respect of taxes on income or on capital relating to the calendar year (including accounting periods beginning in any such year) next following that in which the Convention is signed.

2. The agreement between the Government of Norway and the Government of India for the avoidance of double taxation of income, signed on the 20th July 1959, shall terminate and cease to have effect in respect to taxes on income to which the present agreement applies in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article.

ARTICLE 32

Termination

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination. In such event, this Convention shall cease to have effect:

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given and in respect of capital which is held at the expiry of any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given;
- (b) in Norway, in respect of taxes on income or on capital relating to the calendar year (including accounting periods beginning in such year) next following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in Duplicate at New Delhi this 31st day of December, One thousand nine hundred and eighty six in the Hindi, Norwegian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of
the Republic of India

For the Government of
the Kingdom of Norway

Sd/-

Sd/-

CHAND K. TIKKU

KAARE DAEHLEN

PROTOCOL

At the signing today of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital, the undersigned have agreed upon the following provision which shall form an integral part of the Convention:

1. To Article 16

Where an enterprise engaged in the operation of ships or aircraft in international traffic is carried on

by an unlimited partnership one or more partners of which are residents of a Contracting State and one of more partners of which are residents of the other Contracting State, and the competent authorities of the Contracting States cannot reach agreement as to the question in which of the Contracting States the place of effective management of the enterprise is situated, remuneration dealt with in paragraph 3 of Article 16 may be taxed in the Contracting State in which the recipient is a resident.

2. To Article 25.

The Contracting States agree that paragraph 3 and 4 of Article 25 shall, at the request of Norway, which shall be forwarded by not through diplomatic channels, be replaced by the following text, which shall enter into force on the 30th day upon the confirmation through diplomatic channels of the receipt of that note, and shall apply for the first time in respect of taxes on income or capital relating to the calendar year (including accounting periods beginning in such year) next following that in which the exchange of notes is made :

"3 and 4 :

Where a resident of Norway derives income or owns capital which in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in India, Norway shall allow as a deduction from the income tax or capital tax of that person an amount equal to the tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Norwegian tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income derived from or capital owned in in India."

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed the Protocol.

Done in Duplicate at New Delhi this 31st day of December one thousand nine hundred and eighty six in the Hindi, Norwegian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be operative.

For the Government of the Republic of India For the Government of the Kingdom of Norway

Sd/-

CHAND K. TIKKU

KAARE DEAHLEN

[F. No. 505/3A/81-FTD]

अधिसूचना सं० 7515

धन-कर

सा०का०नि० 757(अ)—केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44क के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नार्वे को उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यक्तिकारी देश घोषित करती है।

[फा.सं. 505/3क/81-एफ टी डी]

पी० के० अपाचू, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION No. 7515

WEALTH TAX

G.S.R. 757(E).—In exercise of the powers conferred by the Explanation to section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby declares Norway to be a reciprocating country for the purposes of that Act.

[F. No. 505/3A/81-FTD]

P. K. APPACHOO, Jt. Secy.

